गाज़ा के एक खेत में टाइल मोज़ैक का एक फर्श मिला है, जिस पर खूबसूरत पक्षी व अन्य जानवर चित्रित हैं। यह इतनी अच्छी स्थिति में है मानो हाल ही में मिट्टी में दबाया गया हो। जैतून की खेती करने वाले किसान, सलमान अल नबाहिन जब बुरेजी रिफ्यूजी कैम्प में जैतून के नए पौधे लगा रहे थे तब उन्हें और उनके पुत्र को यह प्राचीन अवशेष मिला। समझा जाता है कि, यह बायज़ैंटाइन काल का है। असल में कुछ नए पौधे जड़ नहीं पकड़ रहे थे इसलिए जब सलमान और उनके पुत्र ने जमीन खोदनी शुरु की, तब उनके औजार किसी कठोर सतह से टकराए। खोज करने पर उन्हें मोज़ैक का यह फर्श मिला। कोई पुरातत्व विशेषज्ञ आकर देख पाता इससे पहले ही नबाहिन व उनके पुत्र ने इंटरनैट पर खोज शुरु की और मोज़ैक के स्टाइल के आधार पर पता लगाया कि यह संभवतया बायज़ैंटाइन काल का है। बायज़ैंटाइन साम्राज्य रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग था। बायज़ैंटाइन उन कई संस्कृतियों में से एक है, जिसने सदियों तक फिलिस्तीन क्षेत्र पर नियंत्रण रखा। इसके अलावा प्राचीन रोम, मिस्र, ऑटोमन क्रूसेडर स्टेट और बाइबिल कालीन फिलिस्तीन का भी इस क्षेत्र पर प्रभाव था।

हिन्दुस्तान ने रूस के फैसले पर गम्भीर चिंता जताई

रूस ने घोषणा की है कि, वह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में यूक्रेन के साथ हुये अनाज निर्यात समझौते के क्रियान्वयन को तत्काल निलंबित करेगा

- **हिन्दुस्तान ने कहा कि, रूस के एक फैसले के कारण पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहे दुनिया के कई देशों के लिए भुखमरी का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है।**

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे दुनिया के कई देशों पर रूस के एक फैसले से भुखमरी का खतरा और बढ़ गया है। रूस ने शनिवार को कहा था कि वह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए अनाज निर्यात समझौते के क्रियान्वयन को तत्काल निलंबित करेगा। इस समझौते की वजह से यूक्रेन से नौ करोड़ टन से अधिक अनाज का निर्यात हुआ था और वैश्विक स्तर पर खाद्य कीमतों में कमी आई थी। लेकिन अब रूस के फैसले से चिंताएं एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। भारत जैसे मित्र देश ने भी रूस के इस कदम पर चिंता व्यक्त की है।

भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से हुए काला सागर अनाज समझौते को निलंबित किए जाने से दुनिया के सामने मौजूद खाद्य सुरक्षा, ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति संबंधी चुनौतियां और बढ़ने की आशंका है। इस समझौते के तहत रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन से खाद्य सामग्री का निर्यात किया जा रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर आर. मधुसूदन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रयासों के परिणामस्वरूप हुए अनाज समझौते का उद्देश्य वैश्विक खाद्य संकट को टालना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

काला सागर अनाज समझौते पर सोमवार को सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग के दौरान मधुसूदन ने कहा, "काला सागर अनाज समझौते और पक्षों के बीच सहयोग ने अब तक यूक्रेन में शांति के लिए आशा की एक किरण पैदा की थी...हमारा मानना है कि काला सागर अनाज समझौते के निलंबन से दुनिया और विशेष रूप से दक्षिणी हिस्से के सामने खाद्य सुरक्षा, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति चुनौतियां और बढ़ने की आशंका है।" उन्होंने कहा कि भारत "यूक्रेन व रूस से खाद्य एवं उर्वरक के निर्यात की सुविधा शुरू करने और समझौते को नया रूप देकर उसके पूर्ण कार्यान्वयन" की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस की अपील का समर्थन करता है।

रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप में स्थित यूक्रेन के बंदरगाह सेवस्तोपोल में अपने जहाजों पर हमले का हवाला देते हुए शनिवार को समझौता निलंबित करने की घोषणा की थी। गुतारेस ने कहा था कि वह काला सागर अनाज समझौते के संबंध में मौजूदा स्थिति के बारे में बहुत चिंतित हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने चेतावनी दी कि यूक्रेन के अनाज का निर्यात करने के समझौते को रूस द्वारा निलंबित करने से वैश्विक भुखमरी बढ़ेगी। डेलवेयर के विल्मिंगटन में बाइडन ने कहा, "यह वाकई अपमानजनक है। वे क्या कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है।" रूस ने घोषणा की थी कि वह समझौते के क्रियान्वयन को तत्काल रोक देगा। उसने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने शनिवार को रूस के काला सागर बेड़े के जहाजों पर ड्रोन से हमला किया था।

'ठगों की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) पर मंगलवार को आरोप लगाया कि यह पार्टी धोखेबाजों और रिकवरी करने वालों की है।

पार्टी मुख्यालय पर आयोजित एक प्रैस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद धोखेबाज ने "आप" को प्रोटैक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रूपए देने और उसे राज्य सभा सदस्य बनाने के लिए अन्य 50 करोड़ रूपए देने का खुलासा किया है।

उसने दिल्ली के लैफ्टिनैंट गवर्नर को लिखा कि चन्द्रशेखर और दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन तिहाड़ जेल में हैं और आपस में अच्छे मित्र है। वे यह दबाव बना रहे है कि उसने आप को जो पैसा दिया है, उसे सार्वजनिक ना किया जाए।

डा. पात्रा ने कहा कि दिल्ली में आप की क्राइम सिण्डीकेट सरकार चला रही है। इसमें एक तो जेल के भीतर है और दूसरी जेल के बाहर।

उन्होंने कहा कि धोखेबाज सुकेश ने लैफ्टिनैंट गवर्नर को लिखे पत्र में खुलासा किया है कि दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन वर्ष 2015 से उसके मित्र हैं और जैन ने उसे आप का राज्यसभा सदस्य बनाने का वादा किया था। उसने स्वयं को दक्षिण भारत के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करवाने को लेकर "आप" को 50 करोड़ का डोनेशन भी दिया था।

यह दावा करते हुए कि तत्कालीन जेल मंत्री जैन ने उससे मुलाकात करने के लिए तिहाड़ का कई बार दौरा किया और जेल परिसर के भीतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2019 में उससे प्रोटैक्शन मनी भी ली। सुकेश ने दावा किया कि उसने 2 करोड़ की मंथली इन्स्टॉलमैंन्ट के रूप में "आप" को 10 करोड़ रूपए दिए थे। उसने जैन पर यह आरोप भी लगाया कि उनके कहने पर डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ जेल ने उसे धमकियां दी।

दिल्ली में लैफ्टिनैंट गवर्नर द्वारा योगा ट्रेनिंग रोकने को लेकर भी उसने अरविंद केजरीवाल का उपहास करते हुए कहा कि वास्तविकता में केजरीवाल एक ही योग आसन जानते है और वह है "भ्रष्टाचार आसन"।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जरूरतें पूर्ण किए जाने के बाद डेढ़ वर्ष पूर्व लिस्टिंग के लिए तैयार था।

जब यह तथ्य सामने आया कि मंगलवार को लिस्ट हुआ प्रकरण डेढ़ साल से ब्लॉक करके रखा हुआ था तो चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपनी खुद की रजिस्ट्री के लिए ही नोटिस जारी किया।

बैंच की अन्य जज बेला एम. त्रिवेदी थी। नोटिस में रजिस्ट्री को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपना स्पष्टीकरण देने के साथ ही इस प्रकरण को लिस्ट करने में हुए दीर्घकालीन विलम्ब के कारण भी बताए।

कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि वह उन मामलों की भी लिस्ट प्रस्तुत करे जो लिस्टिंग के लिए तैयार हैं लेकिन कोर्ट की सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं है। कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा कि वह यह बताए कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और इसके सुधार के क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं।

यह प्रकरण जिसने सुप्रीम कोर्ट को आक्रोशित किया, उसका संबंध उस मामले से है जो फिलहाल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहा है।

अजमेर दरगाह में अवैध व्यावसायिक निमार्णों पर हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिये

आदेश के अनुसार नगर निगम को कहा गया है कि, दरगाह शरीफ में बनी इन "अनाधिकृत दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें"

-यादवेंद्र शर्मा-

- **जहाँ अनाधिकृत दुकानों का निर्माण हुआ है, वहां निगम ने केवल जनसुविधाओं के लिए नक्शा पास किया था।**
- **पुरानी जनसुविधायें सन् 1917 में निर्मित हुई थीं, जिन्हें तोड़ दिया गया था और फिर 2017 में निगम ने नई जन सुविधायें बनाने का नक्शा पास किया था।**
- **परंतु दरगाह दीवान ने एक प्राइवेट पार्टी से उक्त स्थान पर व्यावसायिक दुकानें बनाने का अनुबंधन कर लिया।**

जयपुर, 1 नवंबर। अजमेर दरगाह शरीफ परिसर के अंदर 16 खंभा क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई जा रही दुकानों पर रोक लगाने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और अनूप कुमार ढंढ की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई।

अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अजमेर दरगाह शरीफ के पूरे क्षेत्र में स्थानीय निकाय की स्वीकृति के बगैर कोई भी व्यसायिक गतिविधि नहीं की जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिये कि निकाय इस जगह का फिर से सर्वे करे और अवैध रूप से बनाई जा रही दुकानों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करे।

इस मामले में सैयद काज़मी चिश्ती द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी और याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी के लिये अधिवक्ता आशीष सक्सैना पेश हुए थे।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशीष सक्सैना ने अदालत को बताया कि दरगाह परिसर में 1917 में फैसिलिटी एरिया बनाया गया था परंतु कई वर्षो से जर्जर हालत में होने के कारण निकाय ने पहले तो इस फैसिलिटी एरिया में निर्मित शौचालयों के उपयोग पर रोक लगाई फिर वर्ष 2017 में 30 से 40 नये शौचालयों और एक वेटिंग रुम का निर्माण करने की योजना पारित की।

बहस के दौरान आशीष सक्सैना ने बताया कि प्राप्त दस्तावेजों से साबित होता है कि दरगाह दीवान ने एक प्राईवेट पार्टी के साथ एम.ओ.यू. किया था, जिसके तहत फैसिलिटी एरिया के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ दुकानों का भी निर्माण किया गया है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि 27 मार्च 2017 में निगम ने जिस फैसिलिटी एरिया के प्लान को स्वीकृति दी थी, उनमें दुकानों का विवरण ही नहीं है।

बहस के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य भी रखे गये कि दरगाह दीवान ने फैसिलिटी एरिया को स्वयं की संपत्ति बताया है, और दरगाह कमेटी का इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है।

अधिवक्ता आशीष सक्सैना ने अदालत के समक्ष निकाय के एक सर्वे की नोटिंग भी प्रस्तुत की जिसमें जे.ई.एन. और एक्स.ई.एन. ने यह बताया है कि मौके पर चार से पांच दुकानों का निर्माण किया गया है।

अदालत ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि दरगाह के पूरे क्षेत्र पर दरगाह कमेटी का अधिकार है और वहीं किसी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव कर सकती है। अदालत ने यह भी आदेश दिये कि निकाय इस क्षेत्र का फिर से सर्वे करे और अगर यह पाया जाए कि वहां पर कॉमर्शियल दुकानें चल रहीं हैं, तो कानून के अनुसार कार्रवाई करे।

यूक्रेन ने रूस को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया

लंदन, 1 नवम्बर (वार्ता)। यूक्रेन में पिछले 24 घंटे के दौरान रूस के एक हजार से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जो रूस के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान और झटका है। समाचार पत्र 'द सन' ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में रूस के करीब एक हजार सैनिक मारे

- **यूक्रेन ने 24 घंटे में रूस के एक हजार से ज्यादा सैनिक मार दिये हैं।**

गए है जो कि रूस के लिए अब तक का सबसे जबरदस्त झटका है।

समाचार पत्र के अनुसार युद्धग्रस्त देश यूक्रेन लगातार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना को पीछे धकेल रहा है और ताजा रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की सेना ने रूस के सैकड़ों सैनिकों का सफाया किया है। यूक्रेन का दावा है कि रविवार को उसने रूस के 950 को मार गिराया है।

गौरतलब है कि आठ महीने पहले शुरू हुए हमलों में यह एक दिन में सबसे ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की घटना है।

इसके साथ ही अभी तक मारे गए रूसी सैनिकों की कुल संख्या 71,200 तक पहुंच गयी है।

तीन नवम्बर को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुआ। इसमें कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। टी.आर.एस. के मंत्री के.टी. रामाराव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि सहानुभूति पाने के लिए भाजपा ने खुद पर ही हमले का षडयंत्र रचा। लेकिन जनता ने उनका खेल समझ लिया है। ट

इसी बीच चुनाव आयोग ने हिंसक घटनाओं को गंभीरता से लिया तथा वहां मौजूद अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने बाहरी लोगों, जो इस चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, से शहर छोड़ने को कहा है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने मीडिया को गैर मतदाताओं को चुनाव क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिए जाने की जानकारी दी।

यहां तीन नवम्बर को मतदान होना है, नतीजे 6 नवम्बर को घोषित होंगे।

चुनाव प्रचार के अंतिम राज्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पुत्र के.टी. रामाराव ने तीव्र प्रचार किया उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा कि "जिस व्यक्ति ने एल.पी.जी. के दाम एक हजार से भी ज्यादा कर दिए हों और जो पैट्रोल 100 रुपए लीटर पर बेचता हो क्या आप उसे वोट देंगे। एकदम ठेठ तेलुगू में बोलते हुए उन्होंने तेलुगू फिल्मों के कई डायलॉग बोले और लोगों से कहा कि वोट देने में बहुत सावधानी बरतें।"

एक सीट से टी.आर.एस. और भाजपा किसी पर फर्क नहीं पड़ेगा। पर दोनों पार्टियों ने इसे जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है क्योंकि उम्मीद है कि इससे अगले वर्ष होने वाले चुनाव की दिशा तय होगी। भाजपा इस जीत को राज्य में अपने लिए संभावनाओं के रुप में देख रही है।

भाजपा नेता केन्द्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने यकीन दिलाया कि पार्टी ना केवल मुनुगोडे सीट जीतेगी बल्कि उसके बाद अगले चुनाव में टी.आर.एस. सरकार को भी उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि टी.आर.एस. का उपचुनाव में हार का डर सता रहा है इसलिए वे हिंसा का सहारा ले रहे है ताकि भाजपा को रोक सकें। उन्होंने कहा कि पुलिस भी टी.आर.एस. से मिली हुई है।

स्वतंत्र पर्यवेक्षकों ने टी.आर.एस. की आसान जीत का दावा किया हालांकि कांग्रेस से भाजपा में गए मौजूदा भाजपा प्रत्याशी भी क्षेत्र के कद्दावर नेता है। इसलिए कांग्रेसी भी उन्हें हराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

ताईवान के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में छः परमाणु बॉम्बर्स तैनात किये

- **एटॉमिक बॉम्बर्स तैनात करके अमेरिका ने चीन को बहुत ही कड़ा संदेश दे दिया है कि, अगर ताईवान में चीन कोई भी चालाकी करता है तो, अमेरिका तुरंत ही अपनी युद्धक प्रतिक्रिया देगा।**
- **अमेरिका के इस कदम से चीन आगबबूला हो गया है और आरोप लगाया है कि, अमेरिका के इस कदम से हमारे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा होगी।**

सिडनी, 1 नवम्बर। अमेरिका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक एयरबेस पर छह परमाणु-सक्षम बी -52 बॉम्बर्स भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी दस्तावेजों का हवाला देते हुए, स्थानीय ब्रॉडकास्टर एबीसी ने बताया कि वॉशिंगटन ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में डार्विन शहर से लगभग 300 किमी दक्षिण में टिंडल एयर बेस पर विमान के लिए समर्पित सुविधाओं के निर्माण के लिए विस्तृत योजना तैयार की थी। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग ने रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन अमेरिकी वायु सेना ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में बॉम्बर्स तैनात करना हमारे विरोधियों को एक मजबूत संदेश भेजता है। अमेरिका के इस कदम से चीन भड़क गया है।

एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह कदम चीन के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि चीन ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। ऐसे में यदि ताइवान में चीन कोई भी चालाकी करने की कोशिश करता है तो फिर अमेरिका इन बॉम्बर्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के बेक्का वासेर ने कहा, "चीन की मुख्य भूमि पर संभावित रूप से हमला करने वाले बॉम्बर्स विमान चीन को एक संकेत भेजने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं यदि चीन ताइवान पर कुछ आगे कार्रवाई करता है तो। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के साथ तनाव ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण डिफेंस सेंटर बना दिया है और इस क्षेत्र में अपनी सैन्य संपत्ति को अपग्रेड करने के लिए 1 अरब डॉलर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विमान निर्माता के अनुसार, बोइंग द्वारा डिजाइन और निर्मित बी-52 अमेरिकी की लिस्ट में सबसे अधिक लड़ाकू-सक्षम बॉम्बर्स हैं। लंबी दूरी के भारी बॉम्बर्स अमेरिकी वायु सेना की रीढ़ रहे हैं और परमाणु व पारंपरिक दोनों हथियारों को तैनात करने में सक्षम हैं। एबीसी ने अमेरिकी वायुसेना के हवाले से कहा कि बॉम्बर्स की मेजबानी करने और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास करने की ऑस्ट्रेलिया की क्षमता दिखाती है कि हमारी दो वायुसेनाएं कितनी एकीकृत हैं।

वहीं, इससे संबंधित पूछे गए एक सवाल में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाने के लिए नहीं है।

ई.वी.एम...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है।" एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमानी ने भी याचिका का विरोध तथा कहा कि व्यक्ति अपनी पसंद ई.वी.एम. तक पहुंचने से पहले ही तय कर लेता है। "चुनाव चिन्ह की जगह फोटो लगाने की मांग करने वाली याचिका से मैं सहमत नहीं हूँ। चुनाव चिन्ह राजनैतिक दलों की पहचान होते हैं।"

दिल्ली के वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दायर की और ई.वी.एम. पर पार्टी के निशान के इस्तेमाल को अवैध, असंवैधानिक तथा संविधान के अनुच्छे 14,15 व 21 का उल्लंघन करार देने की घोषणा करने के लिए निर्देश मांगा। याचिका का कहना है भ्रष्टाचार व राजनीति के अपराधिकरण को हटाने का एक ही तरीका है कि मत पत्र और ई.वी.एम. से पार्टी का निशान हटाकर प्रत्याशी का नाम उम्र व शैक्षणिक योग्यता लिखी जाए। याचिका कहती है कि पार्टी चिन्ह के बिना मतपत्र व ई.वी.एम. होने से मतदाताओं को ईमानदार व योग्य प्रत्याशियों को चुनने में मदद मिलेगी।

वॉट्सऐप ने दो महीने में भारत में 49 लाख अकाउन्ट बैन किये

- **वॉट्सऐप ने इसके पीछे नये आई.टी. रूल्स का हवाला दिया है तथा कहा है कि, जांच में ये अकाउन्ट्स आपत्तिजनक कन्टैंट का प्रसार करते हुये पाये गये हैं।**
- **गौरतलब है कि, वॉट्सऐप भारत में एक सबसे अधिक लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसके देशभर में लगभग 50 करोड़ से अधिक यूज़र्स हैं।**

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। वॉट्सऐप के स्वामित्व वाली कंपनी मैटा ने भारत में 26 लाख से अधिक आपत्तिजनक अकाउन्ट्स को बैन कर दिया है। मंगलवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए कंपनी ने आई.टी. नियम 2021 का हवाला दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत कंटैंट अपलोड एवं प्रसारित किये थे, कंपनी ने सितम्बर के महीने में इन लोगों की मॉनिटरिंग की थी और जांच में पाया गया कि, ये अकाउन्ट बैन किये जाने योग्य हैं।

गौरतलब है कि, वॉट्सऐप भारत में एक सबसे अधिक लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में से एक है, जिसके देशभर में लगभग 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, भारत में सितंबर में 666 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई और 23 शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "आई.टी. नियम 2021 के अनुसार, हमने सितंबर 2022 के महीने की रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस यूजर-सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई का विवरण है, साथ ही, इसमें हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई भी शामिल हैं।"

प्लेटफॉर्म ने अगस्त में भारत में 23 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था। नए आई.टी. नियम 2021 के तहत प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें पांच मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है।

इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और आई.टी. मंत्रालय ने डिजिटल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है। वर्तमान में सोशल मीडिया मध्यस्थों को केवल यूजर्स को गलत कंटेट की कुछ कैटेगिरीज को अपलोड नहीं करने के बारे में सूचित करने की आवश्यकता होती है। यूजर्स को ऐसे कंटेट अपलोड करने से रोकने के लिए उचित प्रयास करना मध्यस्थों का एक कानूनी दायित्व हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि, भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है।

मंत्रालय द्वारा सभी स्टेकहॉल्डर्स को शामिल करते हुए एक विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद संशोधनों को अधिसूचित किया गया था।

रेलवे को इस साल बम्पर कमाई हुई

- **रेलवे की आय में 17 प्र.श. की बढ़ोतरी हुई।**

नई दिल्ली, 1 नवम्बर। रेलवे की माल ढुलाई से आय चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत तक बढ़ गई। रेलवे ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

रेलवे ने बयान में कहा कि अप्रैल-अक्टूबर, 2022 के दौरान उसने माल ढुलाई से कुल 92,345 करोड़ रुपये अर्जित किए जो एक साल पहले के 78,921 करोड़ रुपये की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले रेलवे की माल ढुलाई भी करीब नौ प्रतिशत बढ़ गई।

वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में रेलवे ने कुल 85.56 करोड़ टन वजन की ढुलाई की जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 78.62 करोड़ टन था। वहीं मासिक आधार पर अक्टूबर में रेलवे ने 11.89 करोड़ टन माल की ढुलाई की जो अक्टूबर, 2021 में 11.73 करोड़ टन थी। इस तरह अक्टूबर के महीने में माल ढुलाई में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पिछले महीने में रेलवे ने माल ढुलाई से 13,353 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया जो एक साल पहले के 12,313 करोड़ रुपये की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है। रेलवे ने इसका श्रेय हंग्री फॉर कार्गो योजना को देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धी दरों पर मालवहन सुविधा देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं।

फिल्म स्टार चिरंजीवी एक बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभावहीन हो गए। आंध्र प्रदेश में उनके छोटे भाई पवन कल्याण जो फिल्म स्टार भी हैं, ने भी "जन सेना" नामक अपनी पार्टी बनाई।

यह पार्टी कभी भाजपा के साथ मेल-जोल रखती दिखाई देती है तो कभी-कभार तेलुगूदेशम के साथ।

यही कारण है कि आंध्र प्रदेश में चिरंजीवी की राजनैतिक योजनाओं की चर्चा करना दिलचस्पी भरा है, क्योंकि आंध्र में इस समय वाई.एस.आर. के पुत्र जगन मोहन रेड्डी का शासन है। जिनकी राज्य पर जबरदस्त पकड़ है तथा राज्य की राजनीति में उनका दबदबा है। आंध्र के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ ही होंगे तथा यहाँ से 25 सांसदों की अच्छी-खासी संख्या लोकसभा में जाती है। जहाँ तक संसद का संबंध है, वाई.एस.आर. वहाँ एन.डी.ए. सरकार का समर्थन करती है लेकिन आंध्र प्रदेश में यह क्षेत्रीय दल विस्तारवादी भाजपा का अनुमोदन नहीं करती हैं।

चिरंजीवी की पूर्ववर्ती पार्टी पी.आर.पी. के सदस्य अब अलग-अलग पार्टियों में पहुँच गये हैं। ये सभी लोग मंदिर-नगरी तिरुपति में इकट्ठे हुये तथा इन्होंने अपने सुपर स्टार तथा राजनैतिक गुरु से आग्रह किया कि वे राजनीति में वापस आ जायें। यह फिल्म स्टार स्वयं भी ऐसी चर्चा करते आ रहे हैं जिनसे उनके एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आने के संकेत मिल रहे हैं। उनकी पार्टी के पुराने साथियों तथा उनके निकटस्थ सूत्रों का कहना है कि "उनका आशीर्वाद सदैव ही अपने छोटे भाई तथा उनकी राजनैतिक पार्टी "जन सेना" के साथ है।

दरअसल, जन सेना पी.आर.पी. से ही बनी थी तथा उनके समर्थकों, जिनकी उत्कट इच्छा है कि चिरंजीवी सक्रिय राजनीति में फिर से उतरें का मानना है कि

सरकार ने अपना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस्तेमाल करके ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गत अप्रैल माह में यू-ट्यूब के 22 न्यूज चैनल्स, ट्विटर के तीन, फेसबुक और न्यूज साइट के क्रमशः एक-एक अकाउन्ट को बन्द करने का आदेश दिया था। आई.टी. नियमों की ताजा अधिसूचना जारी कर सरकार डे-टू-डे बेसिस पर कई मुद्दों को कवर करने के लिए प्रकट रूप से संस्थागत फ्रेमवर्क को मजबूत करना चाहती है और साथ ही सोशल मीडिया कम्पनियों को इसके लिए बाध्य करना चाहती है कि वे सैल्स सैन्सरशिप को पहले प्राथमिकता दे।

वायर न्यूज़...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डालकर उनके डिजीटल उपकरण जब्त कर लिए गए।

संयुक्त बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा के नैशनल आई.टी. विभाग के मुखिया की शिकायत पर आतंक मचाया था और इसमें प्रक्रिया का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। एफ.आई.आर. में वायर के संचालकों पर मानहानि, धोखाधड़ी, ठगी और अपराधिक षडयंत्र के आरोप लगाए गए हैं। ये सब आरोप एक न्यूज पोस्ट की वजह से लगाए गए हैं जबकि पोर्टल ने वह न्यूज हटा दी थी। वायर द्वारा जारी बयान के अनुसार क्राइम ब्रांच उनके ऑफिस हाईडिस्क, फोन, आई पैड और कम्प्यूटर ले गई।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908